(ख) रबी 92–93 के दौरान, केन्द्र सरकार ने विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 65.39 करोड़ रुपए निर्मुक्त किये।

अनुर्वर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये अनुसंधान

533. **श्री सोमपाल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया में रिसर्च टू रिक्लेम एरिड लैंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुर्वर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है; और

(ग) अनुर्वर भूमि के उपजाऊ बनाने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि वानिकी, वन चरागाह तथा शुष्क बागबानी के माध्यम से केन्द्रीय मरु शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने बंजर शुष्क भूमियों को खेती लायक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। शुष्क भूमियों को हरी भरी बनाने के लिए खेजरी, बबूल, अनार, बेर जैसे बहुउद्देशीय संबंधी वृक्षों और सेवन घास, अंजन घास जसी घासों की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है।

(ग) हरियाणा, गुजरात तथा राजस्थान के चुने हुए शुष्क जिलों में सूखा-प्रवण क्षेत्र तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा शुष्क भूमि के सुधार से संबंधित कार्य किया जा रहा है।

Production of Oil Seeds

534. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the increase in the area of land brought under oil seeds cultivation, year-wise from 1987-88 to 1992-93 and the increase in oil seeds production in the same period;

(b) what are the main oil seed producing regions in the country;

(c) whether Government would still import edible oil from foreign countries; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a): The year-wise increase of area and production of oilseeds over preceding year is given below:

Year	Increase in Area (million ha.)	Increase In Production (million tonnes)
1987-88	1.50	1.38
1988-89	1.77	5.38
1989-90	0.90	—1.11
1990-91	1.34	1.69
1991-92	1.29	—0.23
1992-93 (Provisional)	0.02	1.72

(b): The main oilseeds producing states are Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Orissa.

(c) and (d): During the current financial year 1992-93 approximately 0.30 lakh tonnes of oil have been imported. In addition approximately 0.47 lakh tonnes of crude Degummed Soyabeen Oil has also been received as a gift under USAID-PL 480 Title-III agreement. Apart from this, there is no proposal at present for further import of edible oil during the current financial year.

Strengthening of Disaster Management Machiery

535. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to strengthen the disaster management machinery for tackling the frequent cyclones affecting the east coast;

(b) what are the steps proposed to reduce the extent of damage due to cyclones on the east coast in particular the coast of Andhra Pradesh; and

(c) present disaster reduction programmes under implementation on the east coast?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a): Yes, Sir.

(b) and (c): A Cyclone Emergency Reconstruction Project aimed at strengthening of institutional capabilities in cyclone preparedness and mitigation is presently under implementation in the coastal areas of Andhra Pradesh with World assistance. Similar projects have also been prepared for the coastal areas of Tamil Nadu and Orissa.

The steps taken to improve the cyclone-warning and forecasting system in the east coast include:—

(i) Expansion of the INSAT based disaster warning system.

(ii) Replacing old Cyclone Detection Radars in a phased manner.

(iii) Installation of High Gust Wind Recorders at Machillipattanam and Karaikal in addition to the existing one at Paradeep.

सूखे से प्रभावित राज्यों के लिये वित्तीय सहायता

536. **श्री सोमपाल :**
श्री शिवचरण सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान देश के कौन-कौन से राज्यों को सूखे से प्रभावित राज्य घोषित किया गया था ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) क्या समस्त राशि वस्तुत: प्रभावित क्षेत्रों में ही खर्च की गई थी ;

(घ) क्या यह सच है कि राजस्थान की कम सहायता राशि दी गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) सूखे की समस्या का स्थायी हल निकालने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) उनका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।